NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 9/2017 –Integrated Tax

G.S.R. 1259(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017- Integrated Tax, dated the 14th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1156(E), dated the 14th September, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63";

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter".

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note: - The principal notification No.8/2017-Integrated Tax, dated the 14th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1156 (E), dated the 14th September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 10/2017- एकीकृत कर

सा.का.नि. 1260 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कराधेय सेवाओं की अंतरराज्यिक पूर्ति करने वाले व्यक्ति को, और जिसका, अखिल भारतीय आधार पर संगणित, सकल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष प्रवर्ग राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, ऐसी पूर्ति का, अखिल भारतीय आधार पर संगणित, सकल मूल्य दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं होगा ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस. एल.,अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 10/2017 – Integrated Tax

G.S.R. 1260(E).— In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making inter-State supplies of taxable services and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, should not exceed an amount of ten lakh rupees in case of "special category States" as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.349/74/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 अक्तूबर, 2017

सं. 11/2017- एकीकृत कर

सा.का.नि.1261(अ).— केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "आईजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 14) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियमों" कहा गया है) के अधीन, उक्त अधिनियम के आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारियों" कहा गया है) होने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं, उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, की बाबत, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 या धारा 55 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के सिवाय इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के लिए उचित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 11/2017 –Integrated Tax

G.S.R.1261(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "IGST Act"), on the recommendations of the Council, the Central Government hereby specifies that the officers appointed under the respective State Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017 (14 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Acts") who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the said Acts (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner of the said Acts, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 20 of the IGST Act, read with section 54 or section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder, except rule 96